Name of the Paper : दैनिक जागरण

Published at : Delhi

Date : 13 NOV 2009

टीवी प्रसारण बाजार में अब दर्शक बनेंगे 'किंग'

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र को किफायती बनाने और दर्शकों को मनचाहा विकल्प चुनने का मौका देने के लिए सरकार ने हेड एंड इन द स्काई (हिट्स) नीति को मंजूरी दे दी है। इस नई तकनीक से देश में केबल टीवी का प्रसारण भी डिजिटल स्वरूप ले लेगा। इतना ही नहीं इससे दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में केबल टीवी के विस्तार का रास्ता खुलेगा। दर्शकों को भी प्रसारण बाजार की प्रतिस्पर्धा के फायदे के रूप में किफायती दरों पर चैनल देखने को मिलेंगे। राष्ट्रकुल खेल-2010 से पहले सरकार हिट्स टीवी प्रसारण को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रही है। केबल और डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) के बाद टीवी देखने के मामले में हिट्स दर्शकों का तीसरा व किफायती माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में हिट्स को

■ शेष पृष्ठ 2 कॉलम 2 पर

टीवी प्रसारण बाजार में अब दर्शक बनेंगे 'किंग'

मंजूरी दी गई। सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि हिट्स प्रसारण उद्योग में लोगों के लिए नया विकल्प होगा। इससे केबल टीवी के प्रसारण का डिजिटलीकरण तो होगा ही, ग्रामीण क्षेत्रों में केबल प्रसारण का द्वार भी खुलेगा। हिट्स के तहत केबल प्रसारक सीधे सेटलाइट से चैनलों के डिजिटल सिग्नल डाउनलोड कर अपने ग्राहकों को पहुंचा सकेंगे। इसमें केबल के मुकाबले टीवी स्क्रीन पर बेहतर प्रसारण देखने को मिलेगा। नई तकनीक से प्रसारण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जहां दर्शकों को इसका फायदा मिलेगा, वहीं केबल प्रसारकों की लागत भी काफी कम रहेगी। चूंकि हिट्स कस्बों और गांवों की राह पकड़ेगा, इसलिए केबल आपरेटर के तौर पर युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। उनका कहना था कि हिट्स आने के बाद केबल आपरेटर बनने की लागत काफी कम होकर 3 लाख रुपये तक आ सकती है। हिट्स के तहत आपरेटर विभिन्न टीवी चैनलों के सिग्नल को अपने सैटेलाइट के जरिए अपलिंक करेगा। केबल आपरेटर इन सिग्नलों को डाउनलिंक कर अपने केबल नेटवर्क के जरिए उपभोक्ताओं तक डिजिटल फार्म में पहुंचा सकेंगे। हिट्स सेवा डीटीएच और मौजूदा केबल से इसी आधार पर अलग होगी। हालांकि इसके लिए भी उपभोक्ता को सेट टाप बाक्स लगाना होगा। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि इस बात पर फोकस रहेगा कि सेट टाप बाक्स की कीमतें न्यूनतम रहें और आसान शर्तों पर उपभोक्ताओं को यह उपलब्ध हो। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दो साल पहले प्रसारण क्षेत्र में हिट्स तकनीक की सिफारिश की थी। सरकार ने काफी गहन चर्चा के बाद अंततः इसे गुरुवार को मंजूरी दी।